Effect of politics on academic performance of students of Sikar district

सीकर जिले के छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर राजनीति का प्रभाव

Vinod Kumar Saini[1], Dr. Sunita Kumari[2]

[1]Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan
[2]Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

सारांश

शिक्षा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानवता के सामाजिक जीवन का इतिहास। जब मनुष्य ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, तो उसने समाज के एकजुट समूह में बने रहने के लिए खुद को व्यवहार के एक निश्चित तरीके में स्थापित करने की कोशिश की। वह चाहते थे कि समाज के युवा भी इन प्रतिमानों का पालन करें। अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत यहीं हुई यानी उनकी बस्तियों के भीतर घर पर। प्रत्येक आदिम समाज में शिक्षा के प्रारम्भ की यही कहानी है। तथ्य यह है कि शिक्षा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह कि शिक्षा और समाज निकटता से संबंधित हैं, यह कोई नया विचार नहीं है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक समाज अपनी परंपरा की रक्षा करता है, अपनी संस्कृति में परिवर्तन को कायम रखता है और परिवर्तनों को स्वीकार करने की इच्छा भी व्यक्त करता है। आधुनिक समाजों में जहां शिक्षा को संरक्षित करने के बजाय ज्ञान को बदलने के बारे में अधिक चिंतित है, जहां यह एक विशेष समूह की संस्कृति को संरक्षित करने के बजाय ज्ञान को एक समाज से दूसरे समाज में व्यापक क्षेत्रों में फैलाना है, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख लक्ष्य हैं, शिक्षा और शिक्षा जब तक शिक्षा प्रणाली समाज के आर्थिक, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चरित्र के केंद्रीय निर्धारक के रूप में एक रणनीतिक स्थान नहीं लेती, तब तक अर्थव्यवस्था बारीकी से तैयार हो जाती है।

मुख्यशब्द इतिहास, सामाजिक, जीवन शिक्षा, संस्कृति समाज, स्थानीय राजनीतिक, सांस्कृतिक ।

प्रस्तावना

अभी हाल तक, भारत के सातवें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, राजस्थान में देश की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों में से एक थी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार, भारत भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों का मूल्यांकन किया गया, राजस्थान के छात्रों ने पढ़ने की समझ, गणित, भाषा और अन्य विषयों में राष्ट्रीय औसत से लगातार नीचे प्रदर्शन किया। 2012-2013 में, सभी विषयों और ग्रेड में, राजस्थान 29 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में से 24वें स्थान पर था। उस निराशाजनक परिणाम ने एक स्पष्ट संदेश दिया: यदि राजस्थान को अपने युवाओं को देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान, कौशल और मानसिकता से लैस करना था - और इस तरह राज्य की जीडीपी में सुधार करना था - तो इसके स्कूल असफल ग्रेड प्राप्त करना जारी नहीं रख सकते थे।

राजस्थान के 80,000 सरकारी स्कूलों में उपकरणों की कमी थी और कर्मचारियों की कमी थी। कई रिक्तियों ने राज्य के शिक्षण और प्रशासनिक रैंक को कम कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाहकार उर्वशी साहनी ने कहा कि हाल तक, राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षण पद और 60 प्रतिशत स्कूल प्राचार्यों के पद रिक्त थे। कई विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। 2014 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, राजस्थान के 37 प्रतिशत ग्रामीण स्कूलों में खेल के मैदानों की कमी है, 26 प्रतिशत में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और 23 प्रतिशत में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है, प्रणाली के लगभग 35 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने स्नातक होने से पहले छोड़ दिया।

कम आपूर्ति में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा के साथ, कम लागत वाले निजी स्कूल विकल्प के रूप में उभरे। मानक *V* (पांचवीं कक्षा) के माध्यम से कक्षा *I* (पहली कक्षा) में निजी स्कूल नामांकन 2008 में लगभग 35 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 46 प्रतिशत हो गया था। कम छात्रों के साथ- निश्चित और सीमित बजट के साथ- सरकारी स्कूलों को प्रति वर्ष अधिक खर्च करना पड़ा है। विद्यार्थियों को उनकी व्यवहार्यता को चुनौती देते हुए समान शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए। हालांकि कुछ परोपकारी संगठन भारत के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एकल मुद्दों को संबोधित करते हैं, जैसे कि लड़कियों को दाखिला देना या शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना। माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन (डेल फाउंडेशन), जिसके पास भारत में शिक्षा निवेश के लिए एक समर्पित पोर्टफोलियो है, और सेंट्रल

स्क्वायर फाउंडेशन (सीएसएफ), जो शिक्षा में विशेषज्ञता रखता है, अधिक समग्र दृष्टिकोण अपना रहे हैं। वे राजस्थान सरकार को सरकारी शिक्षा प्रणाली के मुख्य घटकों, जैसे शासन और जवाबदेही प्रक्रियाओं, स्कूल के बुनियादी ढांचे, और शिक्षक और प्रशासक प्रशिक्षण को मजबूत करने में मदद करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

शिक्षा नीति कार्यान्वयन

शिक्षा के प्रति राजस्थान सरकार का ध्यान और प्रतिबद्धता 4 (चार) शिक्षा नीतियों में देखी जा सकती है, अर्थात्: चरित्र शिक्षा का कार्यान्वयन, डिजिटल स्कूल कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा नीतियां, और निरक्षरता उन्मूलन नीतियों का कार्यान्वयन। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीतियों का कार्यान्वयन इष्टतम नहीं रहा है। इन नीतियों में से तीन एकीकृत नीतियां हैं जिनके विचार और विचार केंद्र से निकलते हैं, अर्थात्: चरित्र शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल स्कूल कार्यक्रम और निरक्षरता उन्मूलन। इस बीच, स्थानीय सरकार द्वारा अनिवार्य कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस्कंदर (व्यक्तिगत संचार, 2020) के अनुसार जिसमें स्थानीय सरकार ने डिजिटल स्कूल नीतियां, निरक्षरता कार्यक्रम, कम उम्र से अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम जारी किए हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों को उनके कार्यान्वयन अवधारणाओं में व्यवस्थित रूप से डिजाइन नहीं किया गया है।

सीकर जिले के स्थानीय निकाय क्षेत्र के छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर राजनीति का प्रभाव

बदलती दुनिया के अस्तित्व के लिए कौशल प्रासंगिक ज्ञान और आदतों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक हथियार है। यह समाज के लिए प्रमुख चिंता का क्षेत्र है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक पहलू को बदलने में मदद करता है। ओकेके (2004) और (2009) मानते हैं कि शिक्षा एक राजनीतिक युद्ध का मैदान है जिसके माध्यम से राजनीतिक गठन अपनी शक्ति और बजटीय आवंटन प्राप्त करता है। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की कुंजी है क्योंकि यह लोगों के सशक्तिकरण की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करती है और समाज में व्यक्तियों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भाग लेने और लाभ उठाने, आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करने और परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करने के लिए तैयार करती है। इसके अलावा, अजय (2016), एल्यूडे आर.ओ.ए., ओखिकु, आई.आई, एसामाह, आई.ओ. और ओजेम्हेंकेले ए. (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि खराब योजना, खराब वित्त पोषण, गलत सांख्यिकीय रिकॉर्ड, खराब जागरूकता और लामबंदी अभियान, स्कूलों में योग्य शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या, प्रशासकों द्वारा धन का गबन, स्कूल की खराब बुनियादी सुविधाएं, खराब प्रावधान शिक्षण

सामग्री की कमी, शिक्षकों की पर्याप्त प्रेरणा की कमी और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा का राजनीतिकरण माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाधाएँ थीं। राजस्थान में, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने के लिए शिक्षा एक उत्कृष्ट साधन है क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि संशोधित राजस्थान संविधान ने शिक्षा को समवर्ती सूची के तहत रखा है जिसका अर्थ है कि संघीय, राज्य और स्थानीय सरकार शिक्षा को उनके आचरण तक नियंत्रित कर सकती है। संवैधानिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। शिक्षा प्रणाली उदाहरण के लिए सरकार की वित्तीय सहायता और संरक्षण के बाहर जीवित नहीं रह सकती है; राजस्थान शिक्षा विकास सरकार से सामाजिक मांग के क्षेत्र में राजनीति द्वारा निर्देशित किया गया है। राजनीति में उन चीजों के आवंटन में शक्ति, प्रभाव और अधिकार का उपयोग और नियमन शामिल है, जो लोग चाहते हैं, इसलिए शिक्षा की राजनीति में शिक्षा शासन में अभिनेताओं के बीच संघर्ष शामिल है, यह बातचीत के पैटर्न या मूल्य, हित और संघर्ष से संबंधित है। शिक्षा और सार्वजनिक प्राधिकरण की अनुभव की आवश्यकता के सापेक्ष लक्ष्य। भारतीय राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने राजनीति को मूल्य, शक्ति और दुर्लभ संसाधनों पर संघर्ष के रूप में परिभाषित किया जिसमें परस्पर विरोधी हितों का उद्देश्य अन्य प्रतिद्वंद्वियों की कीमत पर वांछित मूल्य और संसाधन हासिल करना है। राजनीति को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि किसे क्या, कब, कैसे और कहाँ मिलता है (नवावु 2002)।

सीकर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रभाव शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों और प्रशासकों की नियुक्ति दोनों में परिलक्षित होता है। यद्यपि राजनीति और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता के समय से उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नियुक्ति से संबंधित अधिकांश शैक्षिक निर्णय राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब यह और भी खराब हो गया है। इस संस्कृति ने ग्रामीण स्कूल में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित किया है क्योंकि यहां तक कि शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो योग्य नहीं थे उन्हें ग्रामीण स्कूल में नियोजित किया गया है क्योंकि उनके पास कोई भगवान पिता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता है, यह व्यक्तियों को बाधित कर सकता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से। नियुक्तियों का राजनीतिकरण नासूर बन गया है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर रहा है। समस्या यह है कि सूक्ष्म राजनीति और वृहद राजनीति के बीच परस्पर क्रिया शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक चुनौती कैसे बनती है।

शिक्षा और राजनीति के अब तक के सूक्ष्म और स्पष्ट अंतर्संबंधों पर विचार करने के बाद, इस अध्ययन ने राजस्थान राज्य के सीकर जिले के स्थानीय सरकारी क्षेत्र के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा पर राजनीति के प्रभाव और ग्रामीण छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की जांच की।

सीकर जिले में राजनीतिक भागीदारी पर विद्यालयों का प्रभाव

जबकि हाल के कई अध्ययनों ने युवाओं की नागरिक और राजनीतिक भागीदारी के बारे में चेतावनी दी है, स्कूलों को अक्सर इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उद्धृत किया जाता है। स्कूल न केवल छात्रों को 'वास्तविक' दुनिया के लिए तैयार करते हैं बल्कि वे उन्हें राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। हालांकि, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि स्कूल युवा लोगों की राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुस्तरीय विश्लेषण के माध्यम से फ्लेमिश विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक भागीदारी पर औपचारिक नागरिक शिक्षा, सक्रिय सीखने की रणनीतियों और स्कूल की विशेषताओं के एक साथ प्रभाव की जांच की जाती है। सबूत बताते हैं कि विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा और सक्रिय सीखने की रणनीतियां राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सफल होती हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक भागीदारी का स्तर स्कूल की विशेषताओं पर निर्भर नहीं करता है।

साहित्य में, युवा लोगों की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक पूंजी के बारे में चिंता जताई गई है। कई लेखकों को डर है कि युवा अब स्वैच्छिक संघों या नागरिक जीवन के विभिन्न रूपों में भाग नहीं लेते हैं। अन्य लेखकों ने इस नकारात्मक दृष्टिकोण को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया है कि जहां राजनीतिक भागीदारी के स्तर में गिरावट आ रही है, वहीं भागीदारी के अन्य रूपों के स्तर, जैसे कि सामुदायिक भागीदारी और युवा लोगों के बीच नागरिक भागीदारी बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी एक प्रमुख विषय और सामाजिक सरोकार का मुद्दा बना हुआ है। इस कारण से, तंत्र (जैसे स्कूल की गतिविधियों और विशेषताओं) में नई अंतर्दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है जो युवा लोगों की विशिष्ट राजनीतिक भागीदारी पैटर्न को स्पष्ट और प्रभावित करती है। इस अध्ययन में, यह पता लगाया गया है कि क्या और कैसे स्कूल युवा लोगों की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट की प्रवृत्ति को सुदृढ़ या प्रतिकार कर सकते हैं। गैर-राजनीतिक संस्थान जैसे स्कूल राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों के साथ विद्यार्थियों और छात्रों को तैयार कर सकते हैं। वोल्फिंगर और रोसेनस्टोन (1980, 57), उदाहरण के लिए, तर्क देते हैं कि कॉलेज के छात्र गैर-छात्रों की तुलना में अधिक मतदान करते हैं क्योंकि एक विश्वविद्यालय राजनीतिक रूप से उत्तेजक वातावरण है, जो मतदान की लागत को कम

करता है और भाग लेने के लिए कुछ मानक समर्थन प्रदान करता है। नतीजतन, शिक्षा को युवाओं को 'सार्थक और प्रभावी ढंग से नागरिक जीवन में' संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि स्कूल भागीदारी के एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि स्कूल युवा लोगों की राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं। वेस्टहाइमर और कहेन (2004, 241), उदाहरण के लिए, तर्क देते हैं कि यद्यपि एक सामान्य सहमति है कि नागरिक और लोकतांत्रिक शिक्षा आवश्यक है, इस पर कोई सहमति नहीं है कि 'लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार का स्कूल पाठ्यक्रम इसे बढ़ावा देगा'। स्कूल न केवल औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल के माहौल, साथियों और शिक्षकों के माध्यम से भी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर स्कूलों के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए, औपचारिक नागरिक शिक्षा के अलावा विभिन्न तत्वों पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर भी, जैसा कि वर्बा, श्लोज़मैन और ब्रैडी (1995, 422-3) ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है, 'इस संबंध में अपेक्षाकृत कुछ अनुभवजन्य पूछताछ की गई है कि स्कूली शिक्षा गतिविधि को बढ़ावा क्यों देती है'। इचिलोव (2003, 652), दूसरों के बीच, तर्क देते हैं कि 'विभिन्न प्रकार के अनुभव' के माध्यम से 'भिन्न परिणाम' होते हैं, जो कि स्कूल प्रदान करते हैं, छात्रों की क्षमता और प्रेरणा को स्थिर रखते हुए अनुभव प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, नीमी और सोबिज़ेक (1977, 221) सुझाव देते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का मिश्रण 'स्कूलों के प्रभाव के विभिन्न दृष्टिकोणों की विविधता' पर निर्भर करता है जिनका उपयोग शोध में किया गया है। वास्तव में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्कूल अकेले नहीं खड़े होते हैं: घर के माहौल, सहयोगी जीवन, पसंदीदा मीडिया आदि के बीच एक अंतःक्रिया होती है। अक्सर, स्कूल के माहौल और 'घरेलू माहौल' के बीच एक सकारात्मक संबंध होता है। अंत में, व्हाइटली (2005, 20) का तर्क है कि विभिन्न वर्गों और स्कूली पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों के बीच जटिल संबंधों के कारण, 'भागीदारी जैसे परिणामों के लिए विशेष शैक्षिक विषयों के संपर्क' को जोड़ना समस्याग्रस्त हो सकता है, यह सुझाव देते हुए कि छोटे प्रभाव भी राजनीतिक भागीदारी पर स्कूलों की स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए, हमारे परिणाम वर्गीकरण पर निर्भर हो सकते हैं और ओवरलैप से प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल, एक सरकारी भवन का दौरा औपचारिक शिक्षा के शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसे एक सक्रिय सीखने की रणनीति या खुली कक्षा के माहौल के तत्व के रूप में भी देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का उद्देश्य सीकर जिले के ग्रामीण स्कूलों की घटना का अध्ययन करने के लिए किया जायेगा, जिसमें छात्रों के पढ़ने के प्रदर्शन का एक अनुकरणीय स्तर बनाए रखने के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक सद्भाव के प्रभाव का भी अध्ययन किया जायेगा। सीकर जिले में छात्रों की पाठ्यचर्या पढ़ने की आवश्यकताओं को बदलने के निर्णय से पहले और बाद में छात्रों के प्रदर्शन पर व्यापक चर्चा की गई थी, यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अध्ययन का ध्यान स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियाओं की भूमिका पर था जिसने निर्णय को प्रभावित किया- बनाना। जबकि पाठ्यक्रम में पठन कार्यक्रम का उपयोग और संबंधित सीकर जिला मूल्यांकन परिणाम अध्ययन के अभिन्न अंग थे, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अध्ययन पढ़ने के कार्यक्रम, पढ़ने के निर्देश या सीकर जिले के आकलन पर छात्र के प्रदर्शन के बारे में नहीं था। हालाँकि, इन सभी घटकों ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे स्थानीय राजनीतिक दबावों के आधार पर पाठ्यचर्या परिवर्तन करने के निर्णय के विश्लेषण में माप के स्पष्ट उपकरण थे।

इस अध्ययन में विश्लेषण किए गए आंकड़ों से पता चला कि स्थानीय राजनीतिक दबाव ने सीकर जिले के ग्रामीण स्कूल में शिक्षकों द्वारा गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। सीकर जिले के एक ग्रामीण स्कूल में पठन/ईएलए परीक्षण स्कोर ने संकेत दिया कि जो पाठ्यक्रम मौजूद था और इसे वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ अत्यधिक प्रभावी थीं - यह मानते हुए कि सीकर जिले में सभी छात्रों की 98 प्रतिशत उत्तीर्ण दर मूल्यांकन वांछनीय था और मांगे गए सीखने के स्तर का संकेत था। छात्रों के पढ़ने की आवश्यक मात्रा को कम करने के निर्णय के तुरंत बाद, इस अध्ययन में लागू सांख्यिकीय परीक्षण के कठोर स्तर के अनुसार सीकर जिला-व्यापी मूल्यांकन स्कोर काफी निचले स्तर पर गिर गया। इससे भी बदतर, छात्रों के उपसमूह, जो छात्र निकाय के बहुमत से बने थे- आर्थिक रूप से वंचित छात्र-मूल्यांकन के परिणामों के अनुसार सबसे अधिक पीड़ित थे, और स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूह थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1]। सैक्स, जे.डी. (2018)। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से सतत विकास लक्ष्यों तक। लैंसेट, 379(9832), 2206-2211। डीओआई: 10.1016/एस0140-6736(12)60685-0।

[2]। Bebbington, J., & Unerman, J. (2018)। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना: लेखा अनुसंधान के लिए एक सक्षम भूमिका। लेखा, लेखा परीक्षा और जवाबदेही जर्नल, 31(1), 2-24। डीओआई: 10.1108/एएएजे-05-2017-2929।

[3]। ले ब्लैंक, डी। (2015)। अंत में एकीकरण की ओर? लक्ष्यों के नेटवर्क के रूप में सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास, 23(3), 176-187। डीओआई: 10.1002/एसडी.1582

[4]। कैपरानी, एल। (2016)। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की तुलना में सतत विकास लक्ष्यों के पांच तरीके बेहतर हैं और प्रत्येक शिक्षाविद् को क्यों ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा में प्रबंधन, 30(3), 102-104. डीओआई: 10.1177/0892020616653464

[5]। निल्सन, एम।, ग्रिग्स, डी।, विस्बेक, एम।, रिंगलर, सी।, और मैक्कलम, डी। (2017)। परिचय: सतत विकास लक्ष्य परस्पर क्रियाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा। विज्ञान से कार्यान्वयन तक SDG सहभागिता के लिए एक मार्गदर्शिका। पेरिस: विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद।

[6]। स्टोरी, एम।, किलियन, एस।, और ओ'रेगन, पी। (2017)। जिम्मेदार प्रबंधन शिक्षा: एसडीजी के संदर्भ में क्षेत्र का मानचित्रण। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, 15(2), 93-103। डीओआई: 10.1016/जे.आईजेएमई.2017.02.009।

[7]। मेस्किडे, सी। (2019)। जर्मन स्थानीय सरकारी वेबसाइटों पर सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सूचना प्रसार। सूचना प्रबंधन का एस्लिब जर्नल।

[8]। अन्नान-डायब, एफ।, और मोलिनारी, सी। (2017)। इंटरडिसिप्लिनरिटी: सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, 15(2), 73-83। डीओआई: 10.1016/जे.आईजेएमई.2017.03.006।